

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021—भाद्रपद 5, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जून 2021

क्रमांक एफ 5-09/2020/26.—भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत दिव्यांगजन कल्याण की योजनाओं में एवं संबंधित आगामी समस्त शासकीय कार्यवाहियों हेतु “विकलांग” शब्द के स्थान पर “दिव्यांग” शब्द अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश तिवारी, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जून 2021

क्रमांक-बी-1-1/2021/एक/4.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित अधीक्षक/तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री पंकज स्वरूप टाण्डी	अधीक्षक जिला कार्यालय, मुंगेली	भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन विभाग, दुर्ग.
2.	श्री शंकर लाल सिन्हा	तहसीलदार, बलौदाबाजार-भाटापारा	डिप्टी कलेक्टर, कोंडागांव
3.	श्री मूलचंद चोपड़ा	तहसीलदार, महासमुंद	डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
4.	श्री अरविंद शर्मा	महाप्रबंधक, भू-राजस्व स्मार्ट सिटी लिमिटेड, रायपुर.	डिप्टी कलेक्टर, दंतेवाड़ा
5.	श्री अनुभव शर्मा	तहसीलदार, दुर्ग	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग.
6.	श्री ऋतुराज सिंह बिसेन	तहसीलदार, सरगुजा	परीक्षा नियंत्रक, बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग, बस्तर.
7.	श्री महेश शर्मा	तहसीलदार, जशपुर	डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
8.	श्री संजय विश्वकर्मा	तहसीलदार, कबीरधाम	डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
9.	श्री नंदजी पाण्डेय	तहसीलदार, सूरजपुर	डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
10.	श्री अमित कुमार सिन्हा	तहसीलदार, मुंगेली	डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
11.	श्री रोहित कुमार सिंह	तहसीलदार, कोरबा	डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
12.	श्री उमेश कुमार साहू	तहसीलदार, दुर्ग	उप संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, रायपुर.
13.	श्री प्रवीण तिवारी	सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा.	डिप्टी कलेक्टर, बेमेतरा
14.	श्री हरिओम द्विवेदी	तहसीलदार, मुंगेली	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बिलासपुर
15.	श्री नारायण प्रसाद गबेल	तहसीलदार, बिलासपुर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बिलासपुर
16.	श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू	तहसीलदार, बीजापुर	डिप्टी कलेक्टर, राजनांदगांव
17.	श्री प्रफुल्ल कुमार रजक	तहसीलदार, बेमेतरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर, रामानुजगंज.
18.	श्री राकेश कुमार साहू	तहसीलदार, कोण्डागांव	सहायक, संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर
19.	श्री उत्तमप्रसाद रजक	तहसीलदार, कोरिया	डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर
20.	श्री राकेश साहू	तहसीलदार, गरियाबंद	अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर.
21.	श्रीमती रंजना आहुजा	पुनर्वास अधिकारी, एशियन डेवलपमेंट बैंक परियोजना, लोकनिर्माण विभाग, रायपुर.	पुनर्वास अधिकारी, ए.डी.बी. परियोजना, लोक निर्माण विभाग, रायपुर.
22.	श्री ओमप्रकाश वर्मा	तहसीलदार, गरियाबंद	डिप्टी कलेक्टर, बस्तर
23.	श्रीमती शिवानी जायसवाल	तहसीलदार, सरगुजा	डिप्टी कलेक्टर, सरगुजा
24.	सुश्री रानू मैथ्यूज	तहसीलदार, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर.	प्रबंधक, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर.
25.	श्रीमती रश्मि वर्मा	तहसीलदार, बालोद	डिप्टी कलेक्टर, कबीरधाम
26.	श्रीमती पार्वती पटेल	तहसीलदार, दुर्ग	सहायक संचालक, (तकनीकी) संचाल-नालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर.
27.	सुश्री मोनिका सिन्हा	तहसीलदार, आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर.	उपायुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	श्रीमती इंदिरा मिश्रा	तहसीलदार, बलौदाबाजार-भाटापारा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पेण्ड्रा-मरवाही (जिला कलेक्टर के विकल्प पर).
29.	सुश्री नीता ठाकुर	अधीक्षक, कार्यालय, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण रायपुर.	रजिस्ट्रार, कार्यालय, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायपुर.
30.	श्रीमती तरूणा साहू	प्राचार्य, पटवारी प्रशिक्षण शाला, रायपुर	सहायक संचालक, भू-अभिलेख, रायपुर
31.	सुश्री प्रतिमा ठाकरे	तहसीलदार, बालोद	डिप्टी कलेक्टर, कांकेर
32.	श्री भूपेंद्र सिंह जोशी	तहसीलदार, बिलासपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कोण्डागांव.
33.	श्री नरेंद्र कुमार बंजारा	तहसीलदार, रायपुर	डिप्टी कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा.
34.	श्री टीकाराम देवांगन	तहसीलदार, महासमुंद	डिप्टी कलेक्टर, गरियाबंद
35.	श्री तुलसीदास मरकाम	तहसीलदार, कोरिया	डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
36.	श्री शशिकांत कुरे	तहसीलदार, रायपुर	डिप्टी कलेक्टर, महासमुंद
37.	श्री विजयेंद्र सिंह	तहसीलदार, सरगुजा	भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन विभाग, सरगुजा.
38.	सुश्री रेणुका रात्रे	तहसीलदार, बेमेतरा	सहायक संचालक, कार्यालय, आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर.
39.	श्री घनश्याम सिंह तंवर	तहसीलदार, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर.
40.	श्री अमित बेक	तहसीलदार, रायपुर	सहायक संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
41.	श्री गौतम सिंह	तहसीलदार, बलौदाबाजार-भाटापारा	डिप्टी कलेक्टर, बलरामपुर
42.	श्री शिवनाथ बघेल	तहसीलदार, बीजापुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दंतेवाड़ा.
43.	श्रीमती उमा राज	तहसीलदार, सरगुजा	डिप्टी कलेक्टर, धमतरी
44.	श्री भरत कौशिक	तहसीलदार, बलरामपुर-रामानुजगंज	डिप्टी कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज
45.	श्री शिवकुमार कंवर	तहसीलदार, राजनांदगांव	डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़
46.	श्रीमती ओम विकास टण्डन	तहसीलदार, उपायुक्त, भू-अभिलेख, बिलासपुर.	उपायुक्त (पटवारी प्रशिक्षण शाला) भू-अभिलेख, बिलासपुर.
47.	श्रीमती दिव्या नेताम	तहसीलदार, उत्तर बस्तर कांकेर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानुप्रतापपुर.
48.	श्री अविनाश ठाकुर	तहसीलदार, राजनांदगांव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोण्डी.
49.	श्रीमती रजनी छड़ीमली	अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़	स्टाफ आफिसर, राज्य सूचना आयोग, रायपुर.
50.	सुश्री नेहा भेड़िया	तहसीलदार, रायपुर विकास प्राधिकरण	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर.
51.	श्री हरिशंकर पैकरा	तहसीलदार, बलौदाबाजार-भाटापारा	डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
52.	श्री मनोज कुमार मरकाम	तहसीलदार, उत्तर बस्तर कांकेर	डिप्टी कलेक्टर, सुकमा
53.	श्री राम सिंह सोरी	तहसीलदार, बस्तर	डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर
54.	श्री भूपेन्द्र कुमार गांवरे	तहसीलदार, धमतरी	डिप्टी कलेक्टर, कोण्डागांव
55.	कुमारी हीरा गवर्ना	तहसीलदार, बेमेतरा	डिप्टी कलेक्टर, बेमेतरा
56.	श्री शबाब खान	तहसीलदार, बलरामपुर-रामानुजगंज	डिप्टी कलेक्टर, जशपुर

2. उपरोक्त पदोन्नतियां दो वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी तथा पदोन्नत अधिकारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी।
3. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WP (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other's में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती चित्ररेखा साहू, रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य पद पर नियुक्त करता है।

क्र.	नाम	पद
1.	श्री नरेश ठाकुर, कांकेर	— सदस्य
2.	श्री निखिल द्विवेदी, राजनांदगांव	— सदस्य

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश) को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा सम्यक् रूप से चयनित सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का

पुर्नगठन करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/राजस्व जिला	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायगढ़	रायगढ़	श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा, III व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II एवं जे.एम.एफ.सी. रायगढ़.

No. F 11-3/2013/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, reconstitutes the Juvenile Justice Board by notifying Judge (Principal Magistrate), mentioned in column (4) as Chairman and including Social workers duly selected by the State Level Selection Committee as members for the area mentioned in column (3) of the table below, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue District	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raigarh	Raigarh	Shri Damodar Prasad Chandra, III Civil Judge Class-II & J.M.F.C. Raigarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 1-28/2019/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा 46 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये रायपुर में “भू-संपदा अपीलीय अधिकरण” में अध्यक्ष के पद पर माननीय न्यायाधीश श्री शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त), माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को नियुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 1-28/2019/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 16) की धारा 46 की उप-धारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिये रायपुर में “भू-संपदा

अपीलीय अधिकरण” के लिये सदस्य सिफारिश करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की चयन समिति गठित की जाती है :—

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा मनोनित-मान. न्यायाधीश.
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग.
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2020) के नियम-8 के अधीन बिन्दु 8.5 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक 8.6 अंतः स्थापित करता है :—

“राज्य शासन के समस्त विभागों, उपक्रमों एवं शासनाधीन संस्थाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा स्वयं अथवा अनुबंधित पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप ईकाईयों के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपजों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का क्रय सीधे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ से उनके द्वारा निर्धारित दर पर किया जा सकेगा. इस हेतु पृथक् से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा.”

2. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2021

क्रमांक 3737/एफ-03/28/विविध/2019/14-2.—राज्य शासन, एतद्वारा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (क्र. 23 सन् 2019) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग परिनियम, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त परिनियम में,—

1. परिनियम 10 के खण्ड (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 19 की उप-धारा (3) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 19 की उप-धारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) एवं (घ)” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. परिनियम 17 के शीर्षक में, शब्द “संकायाध्यक्षों की शक्तियां एवं कर्तव्य” के स्थान पर, शब्द “विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की शक्तियां एवं कर्तव्य” प्रतिस्थापित किया जाये.

3. परिनियम 17 के खण्ड (1) में, शब्द “सिफारिशें” के स्थान पर, शब्द, “सिफारिश” प्रतिस्थापित किया जाये.
4. परिनियम 23 के खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

“(5) वित्त समिति”

No./3737/F-03/28/misc/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Viswavidyalaya Adhiniyam, 2019 (No. 23 of 2019), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Viswavidyalaya, Patan, Durg Statutes, 2020, namely :—

AMENDMENT

In the said statutes,—

1. In clause (2) of Statute 10, for the words, figures and symbol “clause (a), (b) and (c) of sub-section (3) of Section 19”, the words, figures and symbol “clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (3) of section 19” shall be substituted.
2. In the title of Statute 17, for the words “Powers and Duties of Deans of Faculties”, the words “Powers and Duties of the Deans of Faculties of University” shall be substituted.
3. In clause (1) of Statute 17, for the words “recommendations”, the word “recommendation” shall be substituted.
4. After clause (4) of Statute 23, the following shall be added, namely :—

“(5) Finance Committee.”

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2021

शुद्धि पत्र

क्रमांक 3739/एफ-03/28/विविध/2019/14-2.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06 मार्च, 2020 में यथा प्रकाशित महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग परिनियम, 2020 संबंधी अधिसूचना क्रमांक/1361/एफ-03/28/विविध/2019/14-2, दिनांक 02 मार्च, 2020 के हिन्दी संस्करण में —

1. परिनियम 2 के खण्ड (क) में, अंक “25” को, “23” पढ़ा जाये.
2. परिनियम 6 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, अंक “3.1” को, “31” पढ़ा जाये.
3. परिनियम 13 में, जहां कहीं भी शब्द “संकायाध्यक्ष” आया हो को, शब्द “संकायाध्यक्ष (डीन)” पढ़ा जाये.
4. परिनियम 20 में, जहां कहीं भी शब्द “मंडल” आया हो को, “बोर्ड” पढ़ा जाये.
5. परिनियम 23 में, शब्द “प्राधिकारियों” को, शब्द “प्राधिकरणों” पढ़ा जाये.
6. परिनियम 35 में, शब्द “अधिकारी-मंडल” को, शब्द “अधिकारी-बोर्ड” पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पेंकरा, संयुक्त सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021

क्रमांक/579/एफ 6-12/36/योजना/2013/2021.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. मछुआ कल्याण बोर्ड में निम्नानुसार उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है :—

1.	श्री राजेन्द्र ढीमर, बिलासपुर	—	उपाध्यक्ष
2.	श्री दिनेश फुटान, रायपुर	—	सदस्य
3.	श्री देव कुंवर निषाद, दुर्ग	—	सदस्य
4.	श्री आर. एन. आदित्य, महासमुंद	—	सदस्य
5.	श्री अमरीका निषाद, कोरबा	—	सदस्य
6.	श्री प्रभु मल्लाह, मुंगेली	—	सदस्य
7.	श्री विजय ढीमर, बेमेतरा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2431/भू-अर्जन/02 अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	अभयपुर प.ह.नं. 17	0.0300	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2432/भू-अर्जन/11 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	चंदननगर प.ह.नं. 12	0.0168	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2433/भू-अर्जन/03 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	रघुनाथपुर प.ह.नं. 13	0.6399	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2434/भू-अर्जन/06 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	केदारपुर प.ह.नं. 14	0.1710	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2435/भू-अर्जन/15 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	ब्रम्हपुर प.ह.नं. 03	0.5059	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2436/भू-अर्जन/08 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	फुलकोना प.ह.नं. 03	0.7950	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2437/भू-अर्जन/14 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	कंचनपुर प.ह.नं. 01	0.6930	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2438/भू-अर्जन/12 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	खजुरी प.ह.नं. 01	0.7219	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2439/भू-अर्जन/16 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	हनुमानगढ़ प.ह.नं. 28	0.2675	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2440/भू-अर्जन/10 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	जगतपुर प.ह.नं. 29	0.4092	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2441/भू-अर्जन/13 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	लब्जी प.ह.नं. 24	0.0852	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज- नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 2 जून 2021

क्रमांक 2442/भू-अर्जन/17 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	त्रिपुरेश्वरपुर प.ह.नं. 22	0.2480	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.),	तारा-प्रेमनगर-रामानुज-नगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रणबीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201611221800001/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	कुहीमाल	0.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800000/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	धौराझोला	1.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800001/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	छैला	3.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800002/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	छैला	4.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800003/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	मुड़गेलमाल	6.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	कुहीमाल	2.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201712221800005/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	स्याहीडोंगरी	3.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201808221800002/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	कुहीमाल	1.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 17 मई 2021

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 201809221800002/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	स्याहीडोंगरी	3.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	छैला व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021

क्रमांक/1182/अ-82/2017-18/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-छोटेकुरुषनार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.435 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1	0.296
18/2	0.139
योग	02
	0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम छोटे-कुरुषनार तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021

क्रमांक/1183/अ-82/2017-18/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोण्डागांव
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-जोड़ेंगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.685 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.057
18/6क, 19, 27	0.091
18/6ख, 19, 28	0.085
18/3	0.133
14/12क	0.191
14/13क, 17	0.138
14/2क	0.365
11/5, 12	0.233
11/4क, 40/4	0.063
6/6	0.053
2/4	0.087
2/7	0.189
योग	12
	1.685

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम जोड़ेंगा तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021

क्रमांक/1184/अ-82/2017-18/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		9/2	0.088
(क) जिला-कोण्डागांव		1/11	0.090
(ख) तहसील-कोण्डागांव		1/2ख	0.140
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेकुरुषनार		1/8	0.140
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.424 हेक्टेयर		1/16	0.115
		1/20	0.110
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	1/5ख	0.101
(1)	(2)	7/4	0.246
		1/12	0.121
52/25	0.121	6/4	0.096
52/30	0.144		
52/8	0.155		
योग	03	11	1.258
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बड़े-कुरुषनार तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बादालूर तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.	

कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021

कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021

क्रमांक/1185/अ-82/2016-17/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

क्रमांक/1186/अ-82/2016-17/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

अनुसूची		(1) भूमि का वर्णन-	
(1) भूमि का वर्णन-		(क) जिला-कोण्डागांव	
(क) जिला-कोण्डागांव		(ख) तहसील-कोण्डागांव	
(ख) तहसील-कोण्डागांव		(ग) नगर/ग्राम-मर्दापाल	
(ग) नगर/ग्राम-बादालूर		(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.128 हेक्टेयर	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.258 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
		138/6क	0.344
9/1	0.011	132/11	0.090

(1)	(2)	अनुसूची	
132/5, 138/9	0.124	(1) भूमि का वर्णन-	
132/5क, 135, 137, 138	0.435	(क) जिला-कोण्डागांव	
132/4, 134	0.012	(ख) तहसील-कोण्डागांव	
88/1, 90/1	0.028	(ग) नगर/ग्राम-करनपुर	
47/1	0.052	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.737 हेक्टेयर	
47/3	0.142	खसरा नम्बर	रकबा
49/1	0.059	(1)	(हेक्टेयर में)
50/1	0.052		
51	0.121	5/6	0.243
38	0.048	5/1ख	0.105
36/2	0.085	4/3क	0.048
36/8	0.089	5/3क	0.020
33/2	0.105	4/5	0.056
32	0.024	8/2	0.064
1/46	0.118	4/4	0.024
39	0.077	9/1ड	0.064
1/44	0.048	9/1घ	0.064
1/84, 30/2	0.061	9/1ख	0.064
		9/1क	0.064
योग	20	13/2	0.093
		9/3	0.380
		31/3क	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम मर्दापाल तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.		33/26	0.170
		33/19ख	0.291
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.		51/1	0.259
		37/8, 52/2ख	0.081
		37/8, 52/3ग	0.198
		37/8, 52/1/क	0.162
		54/2	0.255
कोण्डागांव, दिनांक 13 अप्रैल 2021		योग	21
			2.737

क्रमांक/1187/अ-82/2016-17/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम करनपुर तहसील कोण्डागांव व्यपवर्तन अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरहिंत/2018-21/1737.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज, जिला-रायगढ़ को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिंत घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/17/2018, दिनांक 24 जून, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2021—3 आषाढ़, 1942 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/17/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ के 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 20 फरवरी, 2020 के पत्र सं. 92/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा अपने दिनांक 14 जुलाई, 2020 के पत्र सं. 214/निर्वा.पर्य./2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 17-सारंगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री कृष्ण चंद्र भारद्वाज, ग्राम-गोड़म, तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है.

आदेश से,

हस्ता./—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 24th June, 2021—3 Asadha, 1942 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/17/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 17-Sarangarh Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Krishn Chand Bhardwaj, Independent contesting candidate from 17-Sarangarh Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Raigarh District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 6th February, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Krishn Chand Bhardwaj, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 6th February, 2019 Sh. Krishn Chand Bhardwaj, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Krishn Chand Bhardwaj on 17th February, 2020 Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raigarh vide his letter 92/निर्वा.पर्य./2020 dated 20th February, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raigarh vide his letter 92/निर्वा.पर्य./2020 dated 20th February, 2020, has stated that Sh. Krishn Chand Bhardwaj, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Krishn Chand Bhardwaj, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Krishn Chand Bhardwaj, resident of Village-Godam, Tahsil-Sarangarh, Dist.-Raigarh, Chhattisgarh and the Contesting Independent candidate, for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 17-Sarangarh Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1741.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्रीमती विद्या बाई बघेल, जिला-सूरजपुर को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/04/2018, दिनांक 25 जून, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

नई दिल्ली, तारीख 25 जून, 2021—4 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/04/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती विद्या बाई बघेल, जो छत्तीसगढ़ के 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती विद्या बाई बघेल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती विद्या बाई बघेल को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती विद्या बाई बघेल द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा अपने दिनांक 5 सितम्बर, 2019 के पत्र सं. 2126/निर्वा.सुप./व्यय.अनु./2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर द्वारा, अपने दिनांक 11 अगस्त, 2020 के पत्र सं. 239/निर्वा.सुप./छ.वि.स.चु.-18/ईईएम/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती विद्या बाई बघेल ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती विद्या बाई बघेल निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 4-प्रेमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमती विद्या बाई बघेल, ग्राम-देवनगर, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़, 497333 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 25th June, 2021—4 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/04/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 04-Premnagar Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Smt. Vidya Bai Baghel, an Independent contesting candidate from 04-Premnagar Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Surajpur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Smt. Vidya Bai Baghel for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 14th August, 2019 Smt. Vidya Bai Baghel, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Smt. Vidya Bai Baghel on 28th August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 2126/Ele.Sup./Exp.Sec./2019 dated 5th September 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Surajpur vide his letter No. 239/Ele.Sup./CHLA-18/EEM/2020 dated 11th August, 2020, has stated that Smt. Vidya Bai Baghel, has not submitted any representation or her account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, she has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Smt. Vidya Bai Baghel, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Vidya Bai Baghel, resident of Village-Devnagar, Tahsil-Ramanujnagar, District-Surajpur, Chhattisgarh, 497333 and the Contesting Independent candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 04-Premnagar Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2021

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2018-21/1743.—विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने में असफल रहे श्री महंत जग कुमार शर्मा, जिला-मुंगेली को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/25/2018, दिनांक 01 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

नई दिल्ली, तारीख 1 जुलाई, 2021—10 आषाढ़, 1943 (शक)

सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/25/2018.—यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी.

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महंत जग कुमार शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं.

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महंत जग कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महंत जग कुमार शर्मा को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री महंत जग कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 8 जनवरी, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि.-2018/व्यय लेखा/2020/4404 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा, अपने दिनांक 7 जुलाई, 2020 के पत्र सं. नि.प./वि.स.नि./व्यय लेखा/2019/141 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महंत जग कुमार शर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री महंत जग कुमार शर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :—

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति —

- (i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25-कोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री महंत जग कुमार शर्मा, ग्राम-सिपाही, फास्टरपुर मुंगेली, छत्तीसगढ़ 495334 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है.

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 1st July, 2021—10 Asadha, 1943 (Saka)

No. CG-LA/ES-I/25/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 25-Kota Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 10th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LACH/EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, Independent contesting candidate from 25-Kota Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Bilaspur District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 3rd September, 2019 was issued by Election Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 3rd September, 2019, Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Mahant Jag Kumar Sharma on 27th September, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele./LA Ele. 2018/Exp./2020/4404 dated 8th January, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Bilaspur vide his letter No. Ele/CHLA/Exp/2019 dated 7th July, 2020, has stated that Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :—

“If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Mahant Jag Kumar Sharma, resident of Gram-Sipahi, Fasterpur-Mungeli, Chhattisgarh 495334 and Independent contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 25-Kota Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(NARENDRA N. BUTOLIA)

Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 7 जून 2021

प्रारूप-5

(नियम 11 देखिए)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक 3390/न.ग्रा.नि./शोध/परपोड़ी नि.क्षे./2021.— “परपोड़ी निवेश क्षेत्र” के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26-06-2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है। उक्त अंगीकृत मानचित्र के प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. संभाग आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग (छ.ग.)
2. कलेक्टर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

FORM-V
(See rule 11)

Form for final publication of existing land use map

क्रमांक 3390/न.ग्रा.नि./शोध/परपोड़ी नि.क्षे./2021.—The existing land use map for “Parpodi Planning Area” was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 26-06-2020 and objections and suggestions were invited from the public under the provisions of sub-section (2) of the said section. After giving reasonable opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered desirable, are made therein.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publications in “Chhattisgarh Gazette” under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. the said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of :—

1. Commissioner Durg, Division - Durg (C.G.)
2. Collector, District - Bemetara (C.G.)
3. Joint Director, Town and Country Planning, Regional Office Durg (C.G.)
4. Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat, Parpodi District-Bemetara (C.G.)

हस्ता./—
प्र. संयुक्त संचालक.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

अंतागढ़, दिनांक 6 अप्रैल 2021

उद्घोषणा-पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना राजस्व प्र. क्र./33/अ-82/2016-17,
ऑनलाईन दर्ज प्र.क्र.-201709141400013/31 वर्ष 2016-17
ग्राम कढ़ाईखोदरा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/848/अविअ/रीडर-2/भू-अर्जन/2016-17.—चूंकि नहकसा जलाशय के नहर निर्माण में अर्जित भूमि ग्राम कढ़ाईखोदरा, तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में स्थित भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है, और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिए प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं। अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि वे स्वयं व अपने अधिकारों के साथ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर

कांकेर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 22-04-2021 को प्रातः 11/00 बजे दिन गुरुवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक एवं माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं.	रकबा हे. में	एकड़ में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	कढ़ाईखोदरा अंतागढ़		लच्छनराम पिता मानूराम	पी.आर. एफ. 970, में से	0.48	1.19	एक फसली	निरंक		नहकसा जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु
				पी.आर. एफ. 971 में से	0.52	1.28	एक फसली	निरंक		
				योग	2	1.00	2.47			
2.	कढ़ाईखोदरा अंतागढ़		कुंवरसिंह पिता बीरूराम	पी.आर. एफ. 971 में से	2.11	5.21	एक फसली	निरंक		
				योग	1	2.11	5.21			
				महायोग	3	3.11	7.68			

सी. एल. ओंटी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
एवं भू-अर्जन अधिकारी.